कानपुर, बुधवार, 14 जनवरी, 2026
वर्षः 03, अंकः 17, पृष्ठः 8+4
प्रधान संपादकः पुरुषोत्तम द्विवेदी
सच्चाई के दम पर जोश के साथ...
www.swarajindianews.com
swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews
सांध्यकालीन समाचार पत्र

स्वराज इंडिया

इनसाइड ईरान में खामेनेई शासन के खिलाफ जनविद्रोह...>Pg12
यूनीपोल की अवैध लाइट कटी... > Pg03
मूल्यः 2 ₹

संभल हिंसा मामलाः अदालत-पुलिस आमने-सामने

एसपी की दो टूक... नहीं लिखेंगे FIR

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

- पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश के बाद टकराव गहराया
- एसपी ने स्पष्ट किया कि स्थानीय कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में करेंगे अपील

चंदौसी/संभल। संभल हिंसा से जुड़े एक मामले में चंदौसी की न्यायिक अदालत के आदेश के बाद जिला पुलिस और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। अदालत ने तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार चौधरी (वर्तमान अपर पुलिस अधीक्षक) सहित बारह पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं, जबकि संभल के पुलिस अधीक्षक ने इस आदेश को अवैध बताते हुए साफ कहा है कि मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा।

यह मामला बीते वर्ष जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा से जुड़ा है, जिसमें खग्गूसराय के अंजुमन मोहल्ला निवासी चौबीस वर्षीय युवक आलम को गोली लगने का आरोप है। इस संबंध में मृतक के पिता यामीन ने न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता यामीन के अनुसार 24 नवंबर को उनका बेटा आलम घर से खाद्य सामग्री बेचने के लिए निकला था। उसी दौरान जामा मस्जिद सर्वे के समय हुई हिंसा में पुलिस की गोली उसे लगी। परिजनों का आरोप है कि भय के कारण उन्होंने तत्काल पुलिस से संपर्क नहीं किया और चुपचाप इलाज करवाया। बाद में छह फरवरी 2025 को उन्होंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अनुज चौधरी, कोतवाली के तत्कालीन थानाध्यक्ष अनुज तोमर और दस-बारह अन्य पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने का आरोप लगाया। मामले की सुनवाई के बाद चंदौसी की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने नौ जनवरी 2026 को आदेश दिया कि नामजद और अज्ञात सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विधिक जांच कराई जाए तथा सात दिन के भीतर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

पुलिस अधीक्षक ने किया खुला विरोध

स्थानीय अदालत के आदेश के बाद संभल के पुलिस अधीक्षक केके बिश्नोई ने दो टूक बयान देते हुए कहा कि यह आदेश कानूनसम्मत नहीं है और इस पर अमल नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि संभल हिंसा की न्यायिक जांच पहले ही हो चुकी है, जिसमें पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया गया था। ऐसे में दोबारा मुकदमा दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं है। पुलिस अधीक्षक ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की जाएगी।

डीएसपी अनुज चौधरी का प्रोफाइल भी चर्चा में

इस मामले में जिन अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है, उनमें तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अनुज चौधरी प्रमुख हैं। वर्तमान में वे फिरोजाबाद में ग्रामीण क्षेत्र के अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हैं। वे पूर्व अंतरराष्ट्रीय पहलवान रह चुके हैं और ओलंपिक तथा राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। खेल कोटे से वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए अनुज चौधरी पूर्व में अपने एक सार्वजनिक बयान को लेकर भी विवादों में रहे थे, हालांकि विभागीय जांच में उन्हें बाद में क्लीन चिट मिल चुकी है।

न्यायपालिका और पुलिस के बीच बढ़ता तनाव

स्थानीय अदालत के स्पष्ट आदेश और जिला पुलिस के इनकार के बाद अब यह मामला गंभीर संवैधानिक और प्रशासनिक सवाल खड़े कर रहा है। एक ओर अदालत पीड़ित पक्ष को सुनवाई और जांच का अधिकार दिलाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर पुलिस पहले से हुई जांच का हवाला देकर आदेश को चुनौती दे रही है। कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि अदालत के आदेश के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है, तो यह अवमानना की स्थिति भी पैदा कर सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि उच्च न्यायालय में दायर होने वाली अपील पर क्या रुख अपनाया जाता है और यह टकराव किस दिशा में जाता है। फिलहाल संभल हिंसा से जुड़ा यह मामला केवल एक व्यक्ति की मौत तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह न्यायिक आदेशों के पालन और पुलिस की जवाबदेही जैसे बड़े सवालों का केंद्र बन चुका है।

प्रयागराजः तालाब में डूबने से चार युवकों की मौत

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

- नहाते समय गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा, मुख्यमंत्री ने परिजनों को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए

प्रयागराजः जिले में एक दर्दनाक हादसे में तालाब में डूबने से चार युवकों की मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब सभी युवक तालाब में नहाने गए थे। नहाते समय अचानक वे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया और उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से तालाब में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद चारों युवकों के शव तालाब से

बाहर निकाले गए। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस हृदयविदारक घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना की। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित परिवारों को तत्काल आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए और सभी औपचारिकताएं संवेदनशीलता के साथ पूरी की जाएं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि तालाबों, जलाशयों और अन्य जलस्रोतों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। प्रशासन की ओर से घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।

खौफ की दहशत

अकबरपुर अधिवक्ता समिति की बैठक में विवाद

गोली मारने तक की धमकी

आरोप और प्रत्यारोप व हंगामे के बीच अध्यक्ष की तबीयत बिगड़ी

» घटना को लेकर अधिवक्ता समिति के सदस्यों का कहना है कि सदन की परंपराओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की लगातार अनदेखी की जा रही है

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात।अकबरपुर अधिवक्ता समिति की बैठक मंगलवार को उस समय विवाद का केंद्र बन गई, जब समिति के निवर्तमान अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव पर मनमाने ढंग से भारी धनराशि लेकर नए सदस्यों को शामिल करने और सदन की सहमति के बिना चुनाव अधिकारी नियुक्त करने के गंभीर आरोप लगे। बैठक के दौरान इन आरोपों पर सवाल उठने के बाद माहौल अचानक

अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव को बीपी बढ़ने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया

अधिवक्ता समिति की बैठक में पहुंचे थे पदाधिकारी

तनावपूर्ण हो गया।

बैठक में मौजूद कई अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा बिना सदन की अनुमति के सदस्यता रसीदें काटी गईं और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया।

विरोध बढ़ने पर निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा कथित तौर पर उत्तेजनात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए गंभीर धमकी दिए जाने का आरोप है, जिससे सदन में भारी आक्रोश फैल गया और हंगामे की स्थिति बन गई।

सदन में बढ़ते तनाव के बीच निवर्तमान अध्यक्ष का रक्तचाप बढ़ गया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। स्थिति को देखते हुए समिति के सदस्यों ने उन्हें तत्काल अकबरपुर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों द्वारा उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार बताया गया है।

घटना को लेकर अधिवक्ता समिति के सदस्यों का कहना है कि सदन की परंपराओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की लगातार अनदेखी की जा रही है। आरोप है कि चुनाव अधिकारी की नियुक्ति में सदन की सहमति और एल्डर्स कमेटी की भूमिका को दरकिनार करने का प्रयास किया गया, जिससे समिति की निष्पक्षता और गरिमा पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

इस पूरे घटनाक्रम के बाद समिति परिसर में देर तक चर्चा और बहस का दौर चलता रहा।

अधिवक्ताओं ने मामले के विधिसम्मत और पारदर्शी समाधान की मांग की है। प्रकरण को लेकर अधिवक्ता समुदाय में असंतोष का माहौल बना हुआ है।

वरिष्ठ पत्रकार का निधन, पत्रकारों में शोक की लहर

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और संवेदनशील काव्य रचनाओं के लिए पहचाने जाने वाले जी पी वर्मा का आज सुबह निधन हो गया। वे नेशनल हेराल्ड और हिन्दुस्तान टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में लंबे समय तक कार्यरत रहे और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सशक्त पहचान बनाई।स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें कल शाम चांदनी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से पत्रकारिता जगत और साहित्य प्रेमियों में शोक की लहर दौड़ गई है।उनकी शव यात्रा शीलिंग हाउस स्कूल के निकट स्थित आनंद पैलेस अपार्टमेंट, मकराबर्टगंज से अपराह्न साढ़े तीन बजे भैरोघाट के लिए प्रस्थान करेगी।

सीएम ग्रिड योजना में जल निगम की घोर मनमानी

» घर के मुख्य द्वार के सामने बनाया जा रहा सीवर चेंबर

»प्रमुखता संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर में सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों में गंभीर अनियमितताएं सामने आ रही हैं। ठेकेदारों की मनमानी और जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के कारण स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नियमों को दरकिनार कर कार्य किए जा रहे हैं, जिससे योजना की मंशा पर सवाल खड़े हो गए हैं।

बगिया रोड आवास विकास क्षेत्र में एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी के घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने सीवर चेंबर बनाने के लिए गड्ढा खोद दिया गया। नियमानुसार किसी भी आवासीय भवन के प्रवेश द्वार के सामने इस प्रकार का निर्माण अवैध माना जाता है। पीड़ित निवासी द्वारा बार-बार आपत्ति जताने के बावजूद ठेकेदार ने काम रोकने से इनकार कर दिया।बताया गया कि संबंधित मकान में बुजुर्ग अकेले रहते हैं, जबकि उनके बच्चे बाहर रहते हैं। इसके बावजूद ठेकेदार ने बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए भारी मशीनें लगाकर खुदाई कर दी। मजबूर होकर पीड़ित ने इस अनियमितता की शिकायत जिलाधिकारी से की है। बुधवार सुबह जब दोबारा मशीन लगाई गई तो बुजुर्ग निवासी ने विरोध दर्ज कराया, लेकिन मौके पर कोई जिम्मेदार अधिकारी निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचा।स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग एक हजार इक्कीस करोड़ रुपये की लागत से चल रही इस परियोजना के कारण पिछले एक वर्ष से बगिया रोड के निवासी त्रस्त हैं। सड़क खुदाई के चलते आवागमन बाधित है, वहीं रोजी-रोटी से जुड़े छोटे व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।नगर निगम के जोनल अभियंता आर के सिंह ने बताया कि यह कार्य जल निगम द्वारा कराया जा रहा है, फिर भी नगर निगम की ओर से मौके का निरीक्षण किया जाएगा।सीएम ग्रिड योजना में सामने आ रही इस तरह की मनमानी और अनियमितताओं ने विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिकों ने मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर नियमों के अनुरूप कार्य कराए जाने की मांग की है।

स्वराज इंडिया में खुलासा होते ही एक्शन में नगर निगम

यूनीपोल की अवैध लाइट कटना शुरू

स्वराज इंडिया
खबर का असर

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। नगर निगम कानपुर के विज्ञापन विभाग में यूनीपोल और बस शेल्टर विज्ञापनों को लेकर चल रही कथित अनियमितताओं पर स्वराज इंडिया अखबार में खबर प्रकाशित होने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। खबर के दबाव में पहले ही दिन जोन क्षेत्रों में लगे कुछ यूनीपोल की अवैध लाइट काट दी गई, हालांकि कार्रवाई आंशिक ही नजर आ रही है।

गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा जोन–1 में 35 और जोन–4 में 41 यूनीपोल लगाने के लिए करीब 1 करोड़ 40 लाख का टेंडर निकाला गया था। इस टेंडर को विज्ञापन एजेंसी ठेकेदार पंकज सिंह की अधरित मीडिया फर्म ने करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपये में हासिल कर लिया। इसके बाद शहर के प्रमुख स्थानों पर लगभग 80 यूनीपोल लगाए जा रहे हैं।

सूत्रों का दावा है कि टेंडर की शर्तों में कहीं भी लाइट युक्त यूनीपोल का उल्लेख नहीं था, इसके बावजूद नगर निगम अधिकारियों की कथित मिलीभगत से ठेकेदार द्वारा यूनीपोल में कटिया के माध्यम से बिजली लेकर उन्हें जगमाया जा रहा है। कोकाकोला चौराहा, एलेन हाउस, मुरे कंपनी पुल, कंपनी बाग चौराहा, नवीन मार्केट के पास 2 स्थानों पर, लाल इमली, होटल गीत के पास मॉल रोड सहित कई प्रमुख जगहों पर यूनीपोल लाइट के सहारे चमकते नजर आए।

जब स्वराज इंडिया संवाददाता ने इस पूरे प्रकरण को लेकर विज्ञापन विभाग के प्रभारी विजय सिंह से जानकारी चाही तो वह गोलमोल जवाब देते नजर आए और स्पष्ट स्थिति बताने से बचते रहे।

इतना ही नहीं, नगर निगम के विज्ञापन विभाग में भ्रष्टाचार का दायरा यहीं तक सीमित नहीं है। शहर के करीब 30 बस शेल्टरों पर धड़ल्ले से विज्ञापन डिस्पले लगाए जा रहे हैं, जबकि अधरित मीडिया फर्म को अभी तक इन बस शेल्टरों के लिए वर्क ऑर्डर तक जारी नहीं किया गया है। इसके बावजूद विभागीय संरक्षण में ठेकेदार द्वारा विज्ञापन चलाए जा रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार बस शेल्टरों और चौराहों पर बने ट्रैफिक बूथों में भी नगर निगम की स्ट्रीट लाइट लाइन से बिजली चोरी कर विज्ञापन जलाए जा रहे हैं। ठेकेदार की जेबें तो भर रही हैं, लेकिन नगर निगम की आय ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। स्वराज इंडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद नगर निगम के अधिकारी सक्रिय तो हुए और पहले दिन कुछ यूनीपोल की अवैध लाइट कटवाई गई, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में यूनीपोल और बस शेल्टरों पर नियमों के खिलाफ विज्ञापन जारी हैं।

मार्ग प्रकाश विभाग के सह प्रभारी मुख्य अभियंता आरके पाल ने बताया कि कार्रवाई जारी रहेगी, एजेंसी को नोटिस देकर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह कार्रवाई केवल दिखावटी है या पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। नगर निगम की इस आधी–अधूरी कार्रवाई से साफ है कि अगर मीडिया का दबाव न बने तो शहर में विज्ञापन के नाम पर मनमानी और बिजली चोरी का खेल यूं ही चलता रहता। वहीं इस संबंध में विज्ञापन एजेंसी संचालक पंकज सिंह से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उन्होंने फोन कॉल रिसीव नहीं की।

स्वराज इंडिया || कानपुर सिटी || 03

कटिया की बिजली से जगमगा रहे यूनीपोल!

नगर निगम की स्ट्रीट लाइट से लाइन जोड़कर ठेकेदार लगा रहे नगर निगम और केस्को को भारी चूना

स्वराज इंडिया एक्सक्लूसिव

अफसरों की मिलीभगत से शहर में कई जगह लगे यूनीपोल में चोरी की लाइट का हो रहा प्रयोग

बस शेल्टर के लिए वर्क आर्डर नहीं, धड़ल्ले से लगाए जा रहे डिस्पले

कुशाग्र हत्याकांड: 806 दिन बाद 20 जनवरी को आएगा फैसला

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया न्यूज

- कानपुर के बहुचर्चित कुशाग्र कनोडिया हत्याकांड में 20 जनवरी को एडीजे
- 11 सुभाष सिंह की अदालत में तीनों आरोपियों की किस्मत का होगा फैसला

कानपुर। करीब 806 दिनों तक चली सुनवाई के बाद कानपुर के बहुचर्चित कुशाग्र कनोडिया हत्याकांड में अब न्याय का फैसला आने वाला है। 20 जनवरी को कानपुर जिला न्यायालय में इस सनसनीखेज मामले का निर्णय सुनाया जाएगा। अदालत में अपर सत्र न्यायाधीश–11 श्री सुभाष सिंह द्वारा फैसला सुनाए जाने की पूरी तैयारी है। इस मामले ने न सिर्फ कानपुर बल्कि पूरे प्रदेश, देश और विदेश तक लोगों को झकझोर कर रख दिया था।

कुशाग्र कनोडिया की नृशंस हत्या ने समाज को भीतर तक हिला दिया था। इस हत्याकांड में कुशाग्र की ट्यूशन टीचर रचिता वत्स, उसका प्रेमी प्रभात शुक्ला और दोस्त शिवा गुप्ता को आरोपी बनाया गया। तीनों पर मिलकर साजिश रचने और हत्या को अंजाम देने का आरोप है।

लंबी चली न्यायिक प्रक्रिया

करीब 806 दिनों तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से तमाम गवाह पेश किए गए। कोर्ट में तकनीकी साक्ष्य, परिस्थितिजन्य प्रमाण और गवाहियों के आधार पर बहस पूरी हुई, जिसके बाद अब फैसला सुरक्षित रखते हुए 20 जनवरी की तारीख तय की गई।

फिरोजाबाद हाईवे पर हादसा, बाइक सवार कानपुर के दो युवक जिंदा जले

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक में आग लग गई, जिससे बाइक सवार दो युवक जिंदा जल गए। 5सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।

मृतकों की पहचान कानपुर के चकेरी स्थित शिवकटरा मलिक की बगिया निवासी वैभव और सनिगवां के केआर पुरम निवासी 27 वर्षीय सिद्धार्थ के रूप में हुई है। दोनों गहरे दोस्त थे और एक ही ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी में कार्यरत थे। वैभव कंपनी में कानपुर का मैनेजर था, जबकि सिद्धार्थ टीम लीड के पद पर तैनात था।

- वाहन की टक्कर से बाइक में लगी आग, जिगरी दोस्तों की चली गई जान
- ऑफिस का ताला खुलवाने आगरा जा रहे थे, परिवारों में मचा कोहराम

पहली बार बाइक से निकले थे बाहर

परिजनों ने बताया कि वैभव आमतौर पर लंबी यात्रा ट्रेन या बस से करता था, लेकिन इस बार पहली बार बाइक से जाने का फैसला किया। संयोगवश उनके दोस्त अभय अवस्थी (निवासी मीरपुर कैंट) को भी साथ जाना था, लेकिन बहन के घर खिचड़ी देने फर्रुखाबाद जाने के कारण वह यात्रा में शामिल नहीं हो सका। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। हादसे के कारणों और परिस्थितियों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।

आगरा जा रहे थे, रास्ते में बुझ गई जिंदगी

परिजनों के मुताबिक, दोनों युवक सोमवार शाम करीब तीन बजे बाइक से आगरा के लिए निकले थे। वहां कंपनी का ऑफिस खुलवाना था। वैभव के पिता अवधेश कुमार अवस्थी ने बताया कि सोमवार शाम साढ़े आठ बजे इटावा पहुंचने के बाद बेटे से आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। इसके बाद देर रात सिरसागंज क्षेत्र में हादसे की सूचना पुलिस ने दी।

सचेंडी गैंगरेप: पीड़िता के घर पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय

» पुलिस पर आरोपी दरोगा को बचाने का लगाया आरोप

» 50 लाख मुआवजा, नौकरी और घर देने की उठाई मांग

» स्वराज इंडिया न्यूज

कानपुर। सचेंडी गैंगरेप मामले में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय बुधवार को अचानक कानपुर पहुंचे और पीड़िता के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़िता के पिता से बातचीत कर उन्हें भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता इस कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष करेगा।

अजय राय ने आरोप लगाया कि 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ एक दरोगा ने दुष्कर्म किया, लेकिन पुलिस ने आरोपी को बचाने का काम किया और उसे फरार होने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके पहुंचने से पहले पीड़िता को जबरन घर से हटा दिया और कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाकर बैठा दिया।

अजय राय ने सवाल उठाया कि सरकार आखिर क्या छिपाना चाहती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आरोपी पर इनाम घोषित करना केवल औपचारिकता है, जबकि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए अजय राय ने सरकार से 50 लाख रुपये मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, पीड़िता के लिए पक्का मकान और जमीन देने की मांग की। उन्होंने आरोपी दरोगा की तत्काल गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की भी मांग की। अजय राय ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि जब अन्य आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, तो इस मामले में आरोपी दरोगा के खिलाफ वैसी ही कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।

FOLLOW UP

ड्यूटी के दौरान आरपीएफ जवान की सीने में दर्द से मौत

» कड़ाके की सर्दी और शीतलहर बन रही जानलेवा

» स्वराज इंडिया न्यूज

कानपुर देहात। जनपद में जारी कड़ाके की सर्दी और शीतलहर अब जानलेवा साबित होने लगी है। ठंड के कारण हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार रात रूरा रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान एक आरपीएफ जवान की अचानक सीने में दर्द उठने से मौत हो गई।

रूरा रेलवे स्टेशन स्थित आरपीएफ चौकी में तैनात 58 वर्षीय आरक्षी अशोक कुमार यादव, निवासी विकासनगर जगरथा, इंदरगढ़ जनपद कन्नौज, मंगलवार रात ड्यूटी पर मौजूद थे। इसी दौरान उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द हुआ, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई।मौके पर मौजूद आरपीएफ जवान चंद्रवीर और अन्य सहयोगियों ने उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रूरा पहुंचाया।

वहां तैनात चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उन्हें एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर इमरजेंसी में मौजूद चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना पर अकबरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अकबरपुर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में अत्यधिक सर्दी के कारण अचानक सीने में दर्द उठने से मौत होने की बात सामने आई है।

गौरतलब है कि दिन में धूप निकलने के बावजूद सुबह, शाम और रात के समय पड़ रही कड़ाके की ठंड बुजुर्गों, बच्चों, हृदय और सांस के रोगियों के साथ-साथ रात में खेतों पर काम करने वाले किसानों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही है। हाल के दिनों में सर्दी लगने और सीने में दर्द के बाद मौत के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है।

गीतिका हाइट्स अपार्टमेंट के फ्लैट में लगी भीषण आग

» दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू, जांच शुरू

» स्वराज इंडिया न्यूज

कानपुर। कोहना के गीतिका हाइट्स अपार्टमेंट के छठवें तल पर स्थित फ्लैट नंबर 606 में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। कर्नलगंज फायर स्टेशन की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। कानपुर के कोहना थाना क्षेत्र में गीतिका हाइट्स अपार्टमेंट में बुधवार को भीषण आग लग गई। अपार्टमेंट के एक फ्लैट से अचानक आग की ऊंची लपटें और धुंआ निकलने लगा। अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 606 के बेडरूम में लगी आग को देखकर परिसर में अफरातफरी मच गई। घटना की जानकारी तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद कर्नलगंज फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में दमकल कर्मियों ने मोर्चा संभाला और कुछ ही देर की कड़ी मशक्कत के बाद आग को अन्य कमरों व फ्लैटों में फैलने से पहले ही बुझा दिया।

गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि बेडरूम में रखा काफी सामान जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार, प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। अपार्टमेंट में लगे अग्नि सुरक्षा उपकरणों की भी जांच की जा रही है।

एरियर का भुगतान न किए जाने पर जताया रोष

» स्वराज इंडिया न्यूज

कानपुर। पेंशनर फोरम कार्य समिति की एक आवश्यक बैठक चित्रगुप्त धर्मशाला गोविंद नगर सी ब्लॉक में फोरम के अध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में हुई। जिसमें फोरम के महामंत्री आनंद अवस्थी जी ने बताया कि केंद्र सरकार के समस्त लेखा कर्मचारियों को सेक्रेटेरिएट के समान उच्च वेतन देने का निर्णय वर्ष जनवरी 1996 से देने का निर्णय किया गया जो 18 फरवरी 2003 से नगद भुगतान किया गया।

उन्होंने कहा कि इसके पूर्व काल्पनिक बढ़ोतरी की गई जबकि कोर्ट का आदेश हो गया है कि उसको 1 जनवरी 1996 से एरियर का भुगतान भी किया जाना है उसको न किए जाने पर कार्य कारिणी के सदस्यों ने रोष व्यक्त किया । इसके अतिरिक्त 40ब पेंशन का जो कम्युट की जाती थी जिसका 15 वर्ष बाद दिया जाता था लेकिन अब कोर्ट के आदेश के अनुसार 11 वर्ष 2 माह में रिकवरी बंद करने के आदेश जारी हो चुके है लेकिन इस पर भी अभी तक सरकार द्वारा कोई निर्णय न होने की स्थित मे उपस्थित जनों ने रोष व्यक्त किया इसके अलावा समस्त पेंशनरों में यह शंका व्याप्त है कि जो आठवां वेतन आयोग गठित हुआ है। इस दौरान कार्य समिति ने पी एस बाजपेयी को कार्य कारी अध्यक्ष तथा ओम शंकर तिवारी , विनय प्रकाश उपाध्याय तथा आर पी वर्मा को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इसके पूर्व सीजीएचएस रतन लाल नगर कानपुर में खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। आरपी एस शुक्ला, सत्यनारायण, वी पी श्रीवास्तव, यू एस दीक्षित, आरपी वर्मा, ए एस राठौर, सुभाष भाटिया, के के श्रीवास्तव, एस बी श्रीवास्तव, आर पी एस श्रीवास्तव, शिव शंकर, चंद्र शेखर, जिया लाल, आर बी निनोरिया तथा बजरंगी आदि रहे।

सम्पादकीय

जल प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार जरूरी

निस्संदेह, हरियाणा ने कृषि की उन्नति में नये मानक स्थापित किए हैं। देश की खाद्य सुरक्षा में इस राज्य के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। कृषि क्षेत्र में कारगर रणनीतियों व आधुनिक तकनीकों ने हरियाणा के किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव किया है। लेकिन इससे इतर एक चिंताजनक स्थिति यह है कि राज्य में भूजल संकट एक खतरनाक स्तर को पार कर रहा है। बताया जा रहा है कि राज्य के तीस फीसदी से अधिक गांव भूजल संकट के खतरे की जद में हैं। विडंबना यह है कि इन क्षेत्रों में भूजल का दोहन पुनर्भरण से कहीं अधिक है। जो राज्य में चेतावनी के संकेत स्पष्ट कर रहे हैं। दरअसल, ग्लोबल वार्मिंग संकट के चलते बारिश के पैटर्न में व्यापक बदलाव आया है। जिस अनियमित बारिश को कभी मौसमी समस्या माना जाता था, वह अब एक संरचनात्मक संकट में बदल गयी है। निश्चित रूप से मानसून व बारिश की आवृत्ति में अनिश्चितता के चलते कृषि, पेयजल सुरक्षा व दार्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिये खतरा पैदा हो गया। बारिश की कमी की पूर्ति भूजल के अंधाधुंध दोहन से की जाती है। वैसे इस संकट के मूल में समस्या की वजह पानी की अत्यधिक खपत करने वाला विकास मॉडल भी है। पिछले दशकों में धान व गेहूं की उत्पादकता पर किसानों की निर्भरता अत्यधिक बढ़ी है। जिसमें बहुत सिंचाई की जरूरत होती है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक समीकरणों के चलते किसानों को लुभाने के लिये मुफ्त या रियायती बिजली का चलन भी बढ़ा है। जिससे भूजल के अंधाधुंध दोहन को बढ़ावा ही मिला है। विडंबना यह है जैसे-जैसे भूजल का स्तर गिरता है, ट्यूबवेल हर साल और गहरे खोदे जाते रहे हैं। कोशिश होती रही है कि इससे जल संकट बढ़ने से पानी की कमी पर पर्दा पड़ा रहे। यही वजह है कि इसका नकारात्मक असर आज मध्य और दक्षिण हरियाणा के बड़े क्षेत्र में दिखायी दे रहा है। जहां जलस्तर खतरनाक स्तर तक गिरता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण ने जल संकट को और गहरा कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बहुत तेजी से हुए शहरीकरण ने भूजल का दोहन उसकी स्थायी सीमा से बहुत अधिक हद तक बढ़ाया है। इस बेलगाम भूजल दोहन पर नियामक संस्थाओं की निगरानी ना के बराबर है। वहीं एक चिंताजनक पहलू यह भी है कि तेजी से बढ़ते कंक्रीटीकरण और आर्द्र भूमि के क्षरण से भूजल का प्राकृतिक पुनर्भरण बाधित हुआ है। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तनशीलता, अनियमित मानसून और घटते वर्षा दिवसों ने भूजल पुनर्भरण को और अधिक कम कर दिया है। जिसके चलते जलभंडारों के पुनर्जीवित होने की संभावनाएं लगभग क्षीण हो गई हैं। भूजल स्तर में गिरावट का खमियाजा किसानों को भी उठाना पड़ रहा है। खेतों के लिये सिंचाई जल उपलब्ध कराने की लागत में भी लगातार वृद्धि हो रही है। दरअसल गहरे बोरवेल के लिये अधिक बिजली और अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि ग्रामीण पेयजल योजनाएं स्थिति से निपटने के लिये संघर्ष कर रही हैं। दूसरी ओर कम गुणवत्ता वाले जलभंडारों तक जल-दोहन की स्थिति पहुंचने से प्रदूषण का खतरा बढ़ा है। निस्संदेह, इस संकट को गंभीरता से लेने की जरूरत है। यदि इस सकंट की अनदेखी करके स्थिति को अनियंत्रित छोड़ दिया जाएगा तो इसके व्यापक नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। इससे जहां एक ओर आजीविका का संकट बढ़ेगा, वहीं फसलों को लेकर अस्थिरता होगी और कालांतर जल को लेकर सामाजिक संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। हालांकि, इस संकट के समाधान को लेकर नीतिगत उपाय मौजूद हैं, लेकिन उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत है। फसल विविधीकरण योजनाएं और पुनर्भरण परियोजनाएं सही दिशा में उठाये गए कदम हैं, लेकिन उनका पैमाना और कार्यान्वयन चुनौती के अनुरूप नहीं है। भूजल प्रबंधन, मांग में कमी की तुलना में आपूर्ति बढ़ाने पर अधिक केंद्रित रहा है। निश्चित रूप से हरियाणा को अपनी जल प्राथमिकताओं को तत्काल पुनर्निधारित करने की आवश्यकता है। जरूरत है कम पानी की फसलों को प्रोत्साहित करें, बिजली सब्सिडी युक्तिसंगत बने, शहरी व वाणिज्यिक उपयोग के लिये जल दोहन सख्ती से विनियमित हो व पुनर्भरण क्षेत्रों की रक्षा की जाए।लेकिन इससे इतर एक चिंताजनक स्थिति यह है कि राज्य में भूजल संकट एक खतरनाक स्तर को पार कर रहा है। बताया जा रहा है कि राज्य के तीस फीसदी से अधिक गांव भूजल संकट के खतरे की जद में हैं।

जर्मन पनडुब्बी डील पर चीनी निगाहें

यशवंत सचदेव

जर्मन चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स जब तक भारत में थे, चीन की पूरी निगाहें रक्षा समझौतों पर टिकी हुई थी। चीन की चिंता एशिया-प्रशांत और साउथ चाइना सी में भारत की बढ़ती नेवल पॉवर को लेकर है। 'प्रोजेक्ट 75-आई' के नाम... जर्मन चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स जब तक भारत में थे, चीन की पूरी निगाहें रक्षा समझौतों पर टिकी हुई थी। चीन की चिंता एशिया-प्रशांत और साउथ चाइना सी में भारत की बढ़ती नेवल पॉवर को लेकर है। 'प्रोजेक्ट 75-आई' के नाम से जाना जाने वाला यह समझौता अमल में आया तो भारत की रक्षा खरीद, अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) में एक क्रान्तिकारी बदलाव लाएगा। पहली बार, इस डील में एक कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (टीओटी) शामिल है, जिससे छह टाइप 214 पारंपरिक सबमरीन पूरी तरह से मुंबई में मज़गांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड यार्ड में बनाई जा सकेंगी। जर्मन डील नौसेना के अगली पीढ़ी के 'स्टील्थ' बेड़े पर केंद्रित है। लेकिन, पनडुब्बियों की डील केवल जर्मनी तक सीमित नहीं है। भारत, फ्रांस के साथ तीन अतिरिक्त स्कॉर्पियों क्लास (कलवरी) सबमरीन के लिए 4.3 अरब डॉलर की डील अलग से फाइनल कर रहा है। मौजूदा जर्मन सरकार इस डील को रूसी सैन्य उपकरणों पर भारतीय निर्भरता से दूर करने और बाजार में पैठ बनाने के लिए एक रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में देखती है।

कुछ तकनीकी वजहों से लगभग फ़ाइनल हो चुकी 'प्रोजेक्ट 75-आई' डील की घोषणा नहीं की जा रही है। फ्रीडरिष मैर्त्स की सत्तारूढ़ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सीडीयू) एक मध्य-दक्षिणपंथी पार्टी है, जिसके साथ गठबंधन में क्रिश्चियन सोशल यूनियन (सीएसयू) और ओलाफ शॉल्त्स की मध्य-वामपंथी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसपीडी) शामिल है। इसे जर्मनी में 'काला-लाल गठबंधन' कहते हैं। इस गठबंधन का उद्देश्य आर्थिक विकास और रक्षा खर्च बढ़ाना है। हालांकि, सामाजिक कल्याण के सवाल पर इनमें मतभेद हैं। भले ही मैर्त्स सरकार भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी का समर्थन करती हो, मगर जर्मनी में कुछ राजनीतिक दल, खासकर एसपीडी और ग्रीन्स, हथियारों के निर्यात पर सख्त पाबंदियों की वकालत करते रहे हैं, खासकर नाटो से बाहर के क्षेत्रों में। जर्मन चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स जब तक भारत में थे, चीन की पूरी निगाहें रक्षा समझौतों पर टिकी हुई थी। चीन की चिंता एशिया-प्रशांत और साउथ चाइना सी में भारत ककी बढ़ती नेवल पॉवर को लेकर है। एडवांस्ड टाइप 214 सबमरीन डील को लेकर चीन की भृकुटि तनी हुई है। गत 31 जुलाई, 2025 को चीनी समाचारपत्र ग्लोबल टाइम्स की एक लीड खबर से उसकी चिंता समझी जा सकती है, जिसमें लिखा था, 'भारत अगले हफ़्ते साउथ चाइना सी में युद्धपोत भेजने की योजना बना रहा है। ऐसा क़दम फिलीपींस के लिए समर्थन का 'एक साफ़ संकेत' है।' टॉप नौसैनिक शक्तियों में नंबर वन अमेरिका है। चीन दूसरे नंबर पर और तीसरे स्थान पर रूस है। उसके प्रकारांतर इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, और जापान हैं। भारत सातवां नौसैनिक शक्ति है। एडवांस्ड सबमरीन बनाने के लिए जर्मनी के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर साइन होने से भारत के रक्षा क्षेत्र को ज़बरदस्त बूस्टर डोज़ मिलने वाला है। 'थाईसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स', जर्मनी की सबसे बड़ी नौसैनिक जहाज निर्माता कंपनी है। थाईसेनक्रुप के साथ यह डील छह डीजल पनडुब्बियों के लिए है, जिन्हें एडवांस्ड कन्वेंशनल सबमरीन के नाम से जाना जाता है। तकनीकी ज़रूरतों में से एक यह है कि पनडुब्बियों में एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) टेक्नोलॉजी से लैस है, ताकि ऐसी पनडुब्बियां स्टील्थ क्षमता बढ़ाने के लिए ज्यादा समय तक पानी के अंदर रह सकें। लेकिन सवाल है कि भारतीय नौसेना के लिए टाइप 214 सबमरीन क्यों चाहिए? भारत और रूस की नौसेना के बीच पनडुब्बी प्रौद्योगिकी का लंबा और सफल इतिहास रहा है, जिसमें किलो-क्लास और अकुला-क्लास पनडुब्बियों का बड़ा योगदान है। रूसी पनडुब्बियां अक्सर अन्य पश्चिमी देशों की तुलना में अधिक किफायती रही हैं, जिससे भारत अपने रक्षा बजट के भीतर अपनी क्षमता बढ़ा सका। रूस ने भारत को परमाणु पनडुब्बियों को लीज पर देकर भारत की परमाणु पनडुब्बी क्षमता को बढ़ाने में मदद की है। फिर भी, यह नाकाफ़ी है। यह पनडुब्बी जर्मनी के टाइप 214 डिज़ाइन पर आधारित है, जिसमें एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) टेक्नोलॉजी शामिल है। एआईपी सिस्टम अपने पनडुब्बियों को ऑक्सीजन के लिए बार-बार सतह पर आए बिना, पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक सबमरीन की तुलना में बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर काम करने की अनुमति देते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे सबमरीन दो हफ्ते, या उससे कहीं ज़्यादा समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं, ।

आधुनिक तकनीक से बदलेगी खेती की तस्वीर

ग्रामीण बाजार में वृद्धि

डा0 सुधीर कुमार

देश के छोटे और सीमान्त किसान वर्तमान में भी आधुनिक खेती की तकनीक अपनाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। छोटे किसान ऑनलाइन खरीदारी में दुनिया से बहुत पीछे हैं। ग्रामीण जनजीवन के करीब 22 फीसदी लोगों की कर्ज के लिए साहूकारों और अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता बनी हुई है। भारत में ग्रामीण बाजार शहरी बाजार की तुलना में तेज़ गति से बढ़ रहे हैं। हाल ही में 7 जनवरी को वाहन डीलरों के संगठन फेडरेशन ऑफ़ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (फाड़ा) की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष 2024 में यात्री वाहनों की बिक्री वृद्धि में ग्रामीण बाजार शहरी बाजार से आगे निकल गया। शहरी बाजारों में यात्री वाहनों की बिक्री 8 फीसदी बढ़ी, वहीं ग्रामीण इलाकों में इसमें 12 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2025 में ग्रामीण बाजारों में कुल 44.7 लाख यात्री वाहन बिके, जबकि साल 2024 में कुल 41 लाख वाहनों की बिक्री हुई। उल्लेखनीय है कि भारत के ग्रामीण परिवेश से संबंधित अन्य कई रिपोर्टों में रेखांकित हो रहा है कि किसानों की आमदनी बढ़ने से गांवों में खपत बढ़ रही है और इससे ग्रामीण बाजार को रफ्तार मिल रही है। ग्रामीण गरीबी में कमी, छोटे किसानों की साहूकारी कर्ज पर निर्भरता में कमी और किसानों का जीवन स्तर बढ़ने जैसी विभिन्न अनुकूलताओं से ग्रामीण बाजार मजबूती की राह पर आगे बढ़ रहा है।

किसानों की आमदनी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संगठन नाबार्ड द्वारा 11 दिसंबर को जारी आठवें चरण के ग्रामीण आर्थिक स्थिति एवं भावना सर्वेक्षण (आरईसीएसएस) में बताया गया है कि देश में पिछले एक साल में ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ने से खर्च करने की क्षमता और इच्छा दोनों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। सर्वे के अनुसार 80 फीसदी ग्रामीण परिवारों द्वारा पिछले एक साल में अपनी खपत में वृद्धि की सूचना दी गई है। नाबार्ड के सर्वे के अनुसार, अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में खपत में तेज़ी उम्मीद बढ़ाने वाली है। निवेश और औपचारिक ऋण में भी रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई है जो बढ़ती आय के

समानुपातिक मानी जा सकती है। 29.3 फीसदी ग्रामीण परिवारों ने पिछले एक साल में पूंजीगत निवेश (खेती और गैर-खेती दोनों क्षेत्रों में) बढ़ाया है। बैंक, सहकारी संस्थाओं आदि से कर्ज लेने वाले परिवारों का हिस्सा 58.3 प्रतिशत हो गया, जो कि सितंबर 2024 में 48.7 प्रतिशत था। वस्तुतः ग्रामीण भारत के बाजार के तेजी से बढ़ने के पीछे बढ़ती क्रयशक्ति, वास्तविक आय वृद्धि, जीएसटी सुधार, कम महंगाई और सरकारी योजनाओं के ग्रामीण लोगों को मिलते लाभ भी हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण सुधार, बेहतर कृषि उत्पादन, ग्रामीण वेतन वृद्धि, ग्रामीण उपभोग में बढ़ोतरी तथा कर सुधार जैसे घटकों के दम पर भारत के ग्रामीण बाजार तेजी से आगे बढ़े हैं। इसी तरह दुनिया की प्रसिद्ध एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा प्रकाशित एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 के मुताबिक ग्रामीण भारत में महंगाई घटने और करों में कटौती से भारत की ग्रामीण खपत में सुधार हुआ है। इसी तरह आरबीआई द्वारा प्रकाशित ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण पर आधारित रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में 76.7 फीसदी ग्रामीण परिवारों में उपभोग वृद्धि और 39.6 फीसदी परिवारों में आय में वृद्धि सामने आई है। यही नहीं, गरीबी पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में गरीबी कम हुई है। वर्ष 2019 से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय मजबूती में सहायक बनी है। देश के गांवों में अप्रैल, 2020 से शुरू की गई पीएम स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी जमीन का कानूनी हक देकर उनके आर्थिक सशक्तीकरण का नया अध्याय लिखा जा रहा है। गांवों में किसानों को औपचारिक ऋण से जोड़ने के मद्देनजर सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में वृद्धि महत्वपूर्ण है।

गांवों में बैंक शाखाओं की संख्या मार्च, 2010 के 33,378 से बढ़कर दिसंबर 2024 तक 56,579 हो गई। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सहकारी समितियों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था आदि प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। सरकार ने बीते दशक में फसलों पर दी जाने वाली सब्सिडी और फसल बीमा की राशि को तेजी से बढ़ाया है। भारतीय किसान तेजी से डिजिटल पेमेंट को अपना रहे हैं। वर्ष 2024-25 में भारत में रिकॉर्ड 37.7 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ है तथा देश का कुल कृषि निर्यात 50 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है।

इन सबके बावजूद देश के छोटे और सीमान्त किसान वर्तमान में भी आधुनिक खेती की तकनीक अपनाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं।

पशु अवशेष प्रकरण पर सस्पेंस, निलंबन के बीच ठेका लाइसेंस ने बढ़ाए सवाल

आरोपियों के ठिकानों पर पुलिस दे रही लगातार दबिश, निष्पक्ष जांच के लिए एडीसीपी सुमित रामटेके को सौंपी गई कमान

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर के कुटरा रोड स्थित निर्माणाधीन पानी टंकी के पास कब्रिस्तान और खेत के बीच पशुओं के अवशेष मिलने के मामले में सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। प्रशासनिक कार्रवाई के बीच सामने आए एक ठेका लाइसेंस ने पूरे प्रकरण पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में बिल्हौर इंस्पेक्टर समेत दो दरोगा और एक सिपाही को निलंबित किया जा चुका है। वहीं नगर पालिका चेयरमैन इकलाख खान सहित 10 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ गौहत्या से जुड़ी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस कमिश्नर ने एडीसीपी सुमित रामटेक को बिल्हौर भेजा है। सूत्रों की माने तो मामले की जाँच अधिकारियों ने सुमित रामटेके को सौंपी है। सुमित रामटेक पहले भी बिल्हौर में एसीपी पद पर रह चुके हैं। उन्होंने बिल्हौर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया, पूरे प्रकरण की बारीक जानकारी ली और पुलिस टीम के साथ कई स्थानों पर दबिश दी। सुरक्षा के मद्देनज़र कस्बे के संवेदनशील इलाकों और धार्मिक स्थलों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पीएसी की एक बटालियन भी क्षेत्र में लगातार गश्त करती रही। बिल्हौर तहसील के वकीलों ने प्रतिबंधित मांस के अवशेष मिलने की कठोर निंदा की है। सूबे के

➪ वकीलों ने मुख्यमंत्री को लिखा खत और की नारेबाजी, - हिंदू दल व व्यापार मंडल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उठाए सवाल

मुखिया को खत लिखा और ज्ञापन एसडीएम बिल्हौर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही जमकर नारेबाजी। इधर, घटना के लगभग 24 घंटे बाद जिला पंचायत की ओर से एक ठेका लाइसेंस सामने आया है। जिसमें घटनास्थल पर मिले पशु अवशेषों के निस्तारण का ठेका कानपुर नगर के बेकनगंज निवासी अरशद के नाम होने की बात कही गई है। यह पत्र मंगलवार शाम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिसके बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया। हालांकि आपका अपना स्वराज इंडिया अखबार इस वायरस पत्र की पुष्टि नहीं करता है।अधिकारियों के अनुसार बिल्हौर ब्लॉक क्षेत्र में मृत पशुओं के शवों एवं उनके अवशेषों को सार्वजनिक स्थलों से उठाकर नियमानुसार निस्तारण करने का ठेका अरशद को दिया गया है। ठेका शर्तों में केवल मृत पशुओं के निस्तारण की अनुमति है। बावजूद इसके, जिला पंचायत के पास ऐसी कोई ठोस निगरानी व्यवस्था नहीं है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ठेकेदार नियमों का पालन कर रहा है या नहीं। इसी निगरानी की कमी को लेकर अब प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि बिल्हौर की घटना को गंभीरता से लिया गया है। उच्चाधिकारियों को पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है और जांच के दायरे को व्यापक करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है।उधर खुफ़िया विभाग के अधिकारी सक्रिय होकर। माहौल खराब करने वालों पर नजर बनाए हैं।

गोवंश अवशेष मामले में सांसद सक्रिय

गोवंश के अवशेष मिलने की घटना को लेकर सांसद ने पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर को पत्र लिखकर गहरी चिंता जताई है। पत्र में कहा गया है कि इस तरह की घटनाओं से क्षेत्र में हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है और धार्मिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। सांसद ने विधन और मकनपुर में पूर्व में हुई घटनाओं का भी उल्लेख करते हुए पुलिस प्रशासन पर प्रभावी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। साथ ही गोकशी के मामलों की सघन जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर दोषियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है।

हिंदू दल व व्यापार मंडल ने की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस

मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज हिंदू दल के नेताओं और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मंगलवार को संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अतुल अवस्थी, जिला मंत्री अनुराग यादव, सह जिला मंत्री अनिकेत भदौरिया तथा व्यापार मंडल के पदाधिकारी उदय शंकर मिश्रा मौजूद रहे। नेताओं ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए बड़ी और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। साथ ही पुलिस प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि पुलिस को पिछले छह महीनों से इस मामले की जानकारी थी। उनका कहना है कि उनके कार्यकर्ता मौके पर गए थे, जहां सैकड़ों की संख्या में गौवंश की खाल और अस्थियां मौजूद थीं। भाजपा मंडल अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने कहा कि जिसने भी यह कृत्य किया है, उसे ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं कानपुर ग्रामीण जिला महामंत्री राजेंद्र कटियार ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो तथ्य सामने आए हैं, वे बेहद निंदनीय हैं। दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी भी निर्दोष को फंसाया न जाए।

बिल्हौर थाना प्रभारी बने सुधीर कुमार

बिल्हौर प्रकरण के सामने आने के बाद पुलिस आयुक्त ने प्रशासनिक फेरबदल किया है। बिल्हौर थाने में तैनात थाना प्रभारी अशोक कुमार सरोज के सस्पेंड होने के बाद उनके स्थान पर सुधीर कुमार को बिल्हौर थाने का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में चौबेपुर थाने में भी बदलाव किया गया है। वहां के थाना प्रभारी अशोक चौबे को हटाकर इंस्पेक्टर दुर्गेश मिश्रा को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस प्रशासन के इस कदम को व्यवस्था सुधार और बेहतर कानून-व्यवस्था की दिशा में अहम माना जा रहा है।

बिल्हौर तहसील में लेखपाल संघ की ओर से खिचड़ी भोज

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की उपशाखा बिल्हौर तहसील द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पुरानी तहसील परिसर में जिलाध्यक्ष मोहित सचान, तहसील अध्यक्ष जितेन्द्र यादव एवं मंत्री सुनील चौधरी के नेतृत्व में किया गया।

खिचड़ी भोज में उपजिलाधिकारी संजीव कुमार दीक्षित तथा तहसीलदार अनुभव चंद्र ने पहुंचकर खिचड़ी का वितरण किया और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन में तहसील के समस्त लेखपालों ने सहभागिता की। इसके अलावा तहसील परिसर में मौजूद अधिवक्ताओं, फरियादियों एवं अन्य लोगों ने भी खिचड़ी भोज में भाग लिया। आयोजन सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जहां सभी ने मिल-जुलकर पर्व की खुशियां साझा कीं।

युवाओं ने बढ़ाया मान, मिला सम्मान

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुजरात के सूरत में आयोजित सात दिवसीय युवा अंतर-जनपदीय आदान-प्रदान प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिल्हौर तहसील के युवाओं ने सक्रिय सहभागिता कर जनपद का नाम रोशन किया। भारत सरकार के 'माय भारत' युवा कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित इस प्रशिक्षण में बिल्हौर विकास खंड के नानामऊ गांव निवासी एवं नेहरू युवा मंडल अध्यक्ष हरिओम द्विवेदी ने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट सहभागिता के लिए हरिओम द्विवेदी को सूरत में सम्मानित भी किया गया।

यह कार्यक्रम कानपुर नगर के जिला युवा अधिकारी अनुपम कुमार तथा स्वयंसेवक विनय त्रिपाठी के निर्देशन में संपन्न हुआ।सात दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागी युवाओं ने सूरत के विश्वविख्यात हीरा (डायमंड) उद्योग, आधुनिक बिजनेस मॉडल और विशाल औद्योगिक ढांचे का गहन अध्ययन किया। युवाओं ने हीरा तराशने की इकाइयों का भ्रमण कर कुशल कारीगरों द्वारा हीरों को विभिन्न आकृतियों में ढालने की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा। साथ ही सूरत के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब की कार्यप्रणाली, इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक व्यापारिक नेटवर्क की जानकारी प्राप्त की। 5हरिओम द्विवेदी ने बताया कि सूरत की प्रभावी कार्यप्रणाली और मजबूत बिजनेस स्ट्रेटेजी से प्रेरणा लेकर वे अपने विकास खंड के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के प्रति जागरूक करेंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कानपुर नगर के विभिन्न विकास खंडों से आए सात सदस्यीय दल में हरिओम द्विवेदी के साथ हिमांशु मिश्रा, संगम साहू, सतीश कुमार, हर्षित, अंशू भारती और विकास यादव शामिल रहे।

सरयू की चीख, अफसर की चुप्पी !

» जायसवाल ब्रदर्स की रेत के सहारे सत्ता तक के सफर तय करने की चाह !

डीएमओ-खनन माफिया गठजोड़ से रात के अंधेरों में छलनी हो रही मां सरयू

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी की मर्यादा, आस्था और संस्कृति की दुहाई देने वाला अयोध्या जिला आज एक कड़वे सच से जूझ रहा है। जिस मां सरयू के तट पर रामकथा गूंजती है, उसी सरयू के सीने को रात के अंधेरों में पोकलैंड मशीनों से नोचा जा रहा है। आरोप बेहद गंभीर हैं यह सब जिला खान अधिकारी (डीएमओ) की मिलीभगत और खुले संरक्षण में हो रहा है।

रात के अंधेरे में चलती हैं पोकलैंड मशीन

शिकायतकर्ताओं का दावा है कि जिले के अरबपति खनन माफिया को जिला खनन अधिकारी का खुला संरक्षण प्राप्त है। यही वजह है कि शिकायतों का अंबार लगने के बावजूद कार्रवाई ज़मीन पर नहीं, सिर्फ फाइलों में दौड़ती दिखती है। सूत्रों का सनसनीखेज दावा है कि अवैध खनन के एवज में डीएमओ को प्रतिदिन एक खदान से 50 हजार रुपये 'सुविधा शुल्क' मिलता है। इसी 'सेवा-शुल्क' के दम पर अफसर आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं और सरयू का सीना दिन-रात छलनी किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि खनन माफिया जायसवाल ब्रदर्स ने अवैध खनन के सहारे 500ङ्क600 करोड़ रुपये का काला साम्राज्य खड़ा कर लिया है।

यह साम्राज्य सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं लखनऊ, एनसीआर और गुरुग्राम तक फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि उनकी सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की तैयारी चल रही है। सूत्रों का दावा है कि जिले के एक बड़े सत्ताधारी नेता का खुला संरक्षण इन्हें प्राप्त है। हैरानी की बात है जब मंडलीय खनन अधिकारी से सरेआम मारपीट के बाद भी रेत माफियाओं के हौसले पस्त नहीं होते, बल्कि और बुलंद हो जाते हैं। इससे सीधा सवाल उठता है कि जब अफसर सुरक्षित नहीं, तो नदी और कानून की क्या बिसात? 29 नवंबर 2025 को फतेहपुर सरैया मांझा, तहसील सोहावल में राकेश और सरोज जायसवाल द्वारा मंडलीय खनन अधिकारी अनंत सिंह के साथ मारपीट की जाती है। घटना के बाद कुछ दिन के लिए घाट बंद होते हैं, पोकलैंड मशीनें हटती हैं लेकिन यह सब कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि आंखों में धूल साबित होता है। 11 दिसंबर को निलय, लखनऊ की टीम—घटना के पूरे 12 दिन बाद—जांच को पहुंचती है। 12 दिसंबर 2025ॅ टीम के लौटते ही रात-दिन सरयू के सीने पर अवैध खनन चल रहा है।बीती 11 जनवरी की रात सीयूजी नंबर पर व्हाट्सएप वीडियो भेजकर डीएम, मंडलायुक्त, एडीएम एफआर और खनन निदेशक श्रीमती माला श्रीवास्तव तक शिकायत पहुंचाई गई। वीडियो में साफ दिखता है पोकलैंड मशीनें, रात का अंधेरा और बेलगाम खनन। इसके बावजूद माफियाओं को कोई डर नहीं। शिकायत कर्ताओं का सवाल है कि क्या डीएमओ पर लगे संरक्षण के आरोपों की स्वतंत्र जांच होगी?। इस वायरल वीडियो की पुष्टि स्वराज इंडिया नहीं करता है।

24 घंटे निगरानी संभव नहीं, आरोप निराधार: डीएमओ

अयोध्या के जिला खनन अधिकारी (डीएमओ) आशीष द्विवेदी ने स्पष्ट कहा कि किसी भी खनन क्षेत्र की 24 घंटे निगरानी व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि विभाग को जैसे ही शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाती है। डीएमओ के अनुसार माझा कला क्षेत्र में अवैध खनन नहीं पाया गया, जबकि संतोष जायसवाल के विरुद्ध चार मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से दो मामलों में 6 लाख रुपये और 2,67,048 रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 5,23,912 रुपये का जुर्माना प्रस्तावित है, वहीं 4,13,135 रुपये की रॉयल्टी भी निर्धारित की गई है। डीएमओ ने बताया कि 1742.25 घन मीटर खनन अवैध पाया गया है, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा जुर्माने के बाद अर्थदंड लगाया जाएगा, जिसकी जानकारी अलग से दी जाएगी। डीएमओ ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि विभागीय छापेमारी और कानूनी कार्रवाई लगातार जारी है।

पूर्व आईएएस अधिकारी के 22 वर्षीय बेटे ने की आत्महत्या

दो महीने पहले किया था प्रेम विवाह

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। पूर्व आईएएस अधिकारी चंद्र के 22 वर्षीय बेटे हिमांशु ने अपने आवास पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा और शव परीक्षण के लिए भेज दिया।

परिजनों के अनुसार हिमांशु ने करीब दो महीने पहले ही प्रेम विवाह किया था। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, हालांकि आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।

पुलिस का कहना है कि घटना के समय हिमांशु कमरे में अकेला था। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। दरवाजा तोड़े जाने पर हिमांशु का शव फंदे से लटका मिला।

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव परीक्षण रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के किसी भी तरह के समायोजन पर लगाई रोक

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन -3 मामले में आगे किसी कार्यवाही पर 19 जनवरी तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को नियत करके अंतरिम आदेश दिया कि मामले की इस अगली सुनवाई की तिथि तक बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर, समायोजन -3 मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि इस अंतरिम आदेश की राहत, इस याचिका के साथ संबद्ध 11 अन्य याचिकाओं के याची शिक्षकों को भी उपलब्ध होगी। कोर्ट ने यह आदेश प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन/ स्थानांतरण - 3 के शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिया।

न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश बाराबंकी की संगीता पाल समेत 29 प्राथमिक शिक्षकों की याचिका पर दिया। याचिकाओं में 14 नवंबर 2025 के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी शिक्षकों के समायोजन/ स्थानांतरण के शासनादेश को चुनौती देकर रद्द करने का आग्रह किया गया है। याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच जी एस परिहार का कहना था कि यह शासनादेश आर टी ई अधिनियम समेत बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1981 के नियमों का उल्लंघन करने वाला है। इसके नियम 21 के तहत शिक्षक की सहमति के बाहर समायोजित न किए जाने की दलील दी। कहा इस समायोजन से जहां शिक्षकों की वरिष्ठता पर असर पड़ रहा है, वहीं अन्य विसंगतियां भी पैदा हो रही हैं।

उधर, मामले में राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता के आग्रह पर कोर्ट ने मामले को 19 जनवरी को फाइनल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस बीच याचियों को मामले में अंतरिम राहत प्रदान की है। साथ ही राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने का समय दिया है।

जाम के झाम से मुसीबत में रसूलाबाद के वाशिंदे

मुख्य चौराहे से गुजरना बना चुनौती, ई-रिक्शा व ऑटो चालकों की मनमानी से हालात बदतर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रसूलाबाद कस्बे में जाम की समस्या दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि लोग मुख्य चौराहे से गुजरने से कतराने लगे हैं। थोड़ी सी भी लापरवाही या भीड़ के चलते घंटों जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे आमजन के साथ-साथ राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पीआरडी के जवान मुख्य चौराहे पर तैनात रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वाहन चालक यातायात नियमों की खुलेआम अनदेखी कर रहे हैं। गलत साइड से वाहन निकालने और सड़क पर अव्यवस्थित तरीके से खड़े होने के कारण जाम की समस्या और विकराल हो जाती है। कस्बे के बिल्हौर मार्ग स्थित मुख्य चौराहे पर ई-रिक्शा चालकों की मनमानी जाम का बड़ा कारण बनी हुई है। सवारी भरने की होड़ में चालक सड़क पर ही ई-रिक्शा खड़ा कर देते हैं। कई बार एक साथ 20-20 ई-रिक्शा चौराहे पर खड़े नजर आते हैं, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो जाता है।

क्या बोले ईओ..

इस संबंध में अधिशासी अधिकारी कुलकमल सिंह ने बताया कि पुलिस प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण करने वालों को पहले नोटिस दिया जाएगा, इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए जाम की समस्या का शीघ्र समाधान कराया जाएगा।

गौरतलब है कि जिस स्थान पर वर्तमान में ई-रिक्शा खड़े होते हैं, वहां पहले बिल्हौर जाने वाली प्राइवेट बसों का स्टैंड था। जाम की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने बस स्टैंड को तहसील गेट के पास स्थानांतरित कर दिया था, लेकिन ई-रिक्शा चालकों ने उसी स्थान को अपना अड्डा बना लिया, जिससे स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसके अलावा दिन के समय विभिन्न मार्गों से बड़े ट्रेलर और भारी वाहन भी कस्बे के अंदर से गुजरते हैं, जिससे मुख्य चौराहे पर लंबा जाम लग जाता है। तहसील और कोतवाली जाने वाले लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो भविष्य में कस्बे के लिए रिंग रोड की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि भारी वाहन बाहर से ही निकल सकें और कस्बे को जाम से राहत मिल सके।

नाबालिग किशोरी लापता, पुलिस कर रही तलाश

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। थाना मंगलपुर क्षेत्र के चक्केपुरवा गांव से एक नाबालिग किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।

चक्केपुरवा गांव निवासी अर्चना ने थाना मंगलपुर में दी गई तहरीर में बताया कि पति की मृत्यु के बाद वह अपने बच्चों के साथ मायके चक्केपुरवा में रह रही हैं। बीती 5 जनवरी को उनकी नाबालिग पुत्री घर से कहीं चली गई। काफी देर तक वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक महेश कुमार ने बताया कि किशोरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और उसकी तलाश की जा रही है।

रॉन्ग साइड से जा रहे ट्रैक्टर से तेज रफ्तार बोलेरो टकराई, बाल-बाल बचे

» पुलिस ने क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर और बोलेरो को क्रेन से हाईवे से हटवाया

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

कानपुर देहात। रनिया थाना क्षेत्र में मंगलवार रात एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। पड़ाव चौराहा के पास रॉन्ग साइड से जा रहे ट्रैक्टर की तेज रफ्तार बोलेरो कार से आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो कार के परखच्चे उड़ गए, हालांकि गनीमत रही कि वाहन में सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए।

जानकारी के अनुसार, बोलेरो कार में मेटलकैन्स फैक्ट्री के मजदूर व कर्मचारी सवार थे, जो अकबरपुर की ओर से आ रहे थे। इसी दौरान गलत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर ने बोलेरो को टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही रनिया पुलिस मौके पर पहुंची।

पुलिस ने क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर और बोलेरो को कब्जे में लेकर क्रेन की मदद से हाईवे से हटवाया, जिससे यातायात सुचारु रूप से बहाल किया जा सका। इस संबंध में थाना प्रभारी रनिया शिव नारायण सिंह ने बताया कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। ट्रैक्टर चालक की पहचान प्रमोद निवासी मनेथू गांव के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विशेष ट्रेनिंग लेकर वापस लौटे आपदा मित्र

कानपुर देहात के 32 स्वयंसेवक ट्रेनिंग लेने गए थे

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात ।कानपुर देहात जनपद के 32 स्वयंसेवक आपदा मित्र प्रशिक्षण प्राप्त कर लखनऊ से वापस लौट आए हैं।

आपदा विशेषज्ञ अश्वनी वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 जनवरी 2026 को जनपद से चयनित स्वयंसेवकों को राज्य आपदा मोचक बल (एसडीआरएफ) द्वारा आयोजित 12 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण हेतु लखनऊ भेजा गया था।प्रशिक्षण के दौरान आपदा मित्रों को अग्निकांड, बाढ़, भूकंप, सर्पदंश, आकाशीय विद्युत (वज्रपात), प्राथमिक उपचार सहित विभिन्न आपदाओं से निपटने की व्यावहारिक एवं तकनीकी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण उपरांत सभी प्रतिभागियों को बहुउपयोगी आपदा राहत किट प्रदान की गई

तथा एसडीआरएफ द्वारा प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले आपदा मित्रों में कादिर खान (कमांडर) ,आशीष सिंह चौहान, हमजा सिद्दीकी, विकास, राकेश कुमार , विशाल, शिवा सहित अन्य स्वयंसेवक शामिल रहे। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद ये आपदा मित्र अब आपातकालीन परिस्थितियों में जनसहायता के लिए पूरी तरह सक्षम होंगे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक:** अनूप कुमार **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 l **Email:** swarajindia2023@gmail.com l **Mob:** 7800009853, l **Website:** www.swarajindianews.com l **(समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)** प्रादेशिक कार्यालय:4ए/5,119/10बी, खान बिल्डिंग, पार्क रोड हजरतगंज

श्री द् यूल बाबा 11वें वार्षिक क्रिकेट टूर्नामेंट की कल से होगी शुरुआत

» फाइनल में प्रथम व द्वितीय विजेता टीम को मिलेगी पल्सर बाइक

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। विकास खंड मलासा के पुलन्दर गांव में श्री द् यूल बाबा क्रिकेट क्लब के तत्वधान में कल से विशाल 11वें वार्षिक क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन 15 जनवरी से किया जाएगा। मकर संक्रांति पर शुरू होने वाला यह टूर्नामेंट रोमांच और खेल भावना से भरपूर होने वाला है। आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह(विकास भैया) ने बताया कि इस वर्ष का टूर्नामेंट पहले से कहीं अधिक बड़े स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है। टूर्नामेंट में 20-20 ओवर का प्रारूप रखा गया है, जिसमें कुल 16 टीमें प्रतिभाग कर सकेंगी। पुलंदर गांव की प्रधान प्रीति तिवारी और प्रतिनिधि वीके तिवारी ने बताया कि फाइनल मुकाबले में प्रथम विजेता टीम को पल्सर बाइक150 सीसी एवं द्वितीय विजेता टीम को भी पल्सर बाइक 125 सीसी पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। टूर्नामेंट की एंट्री फीस 11,000 रुपये निर्धारित की गई है। टूर्नामेंट का उद्घाटन समाजसेवी राघवेंद्र सिंह भदौरिया एवं ग्राम प्रधानप्रतिनिधि वीके तिवारी द्वारा ही किया जाएगा। उद्घाटन मैच पहले दिन घार बनाम जय बड़े देव बाबा टीम के बीच खेला जाएगा। सोनू भदौरिया ,पंकज तिवारी, गौरव ठेकेदार, आदि लोग मौजूद रहे।

रनियां में अवैध खनन की मिट्टी से भरे तीन डंपर सीज

राजस्व विभाग, खनन विभाग और रनियां पुलिस की संयुक्त टीम ने मारा छापा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। कानपुर देहात की पुलिस अब लगातार मिट्टी खनन माफियों की कमर तोड़ रही है।

जिससे साफ अब दिख रहा है मिट्टी खनन में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत रनियां थाना क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। राजस्व विभाग, खनन विभाग और रनियां पुलिस की संयुक्त टीम ने गोईनी गांव में छापेमारी कर मिट्टी से लदे तीन डंपरों को सीज कर दिया।

अधिकारियों के अनुसार, बिना अनुमति खनन और अवैध परिवहन की लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। मौके पर टीम द्वारा खनन से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई, लेकिन कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

इसके बाद तीनों डंपरों को सीज करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक शिवनारायन सिंह ने बताया कि अवैध रूप से मिट्टी का खनन व परिवहन करने वाले तीन डंपरों को सीज किया गया है।

उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि थाना क्षेत्र में अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

और भविष्य में भी इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे।

कानपुर देहात डीएम ने जनसुनवाई में सुनीं लोगों की शिकायतें

जाति प्रमाण पत्र न बनने पर तहसीलदार को दिए त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई की। उन्होंने आमजन की विभिन्न शिकायतें गंभीरता से सुनीं और संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध, पारदर्शी तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों का प्राथमिकता के आधार पर संतोषजनक निस्तारण किया जाए। उन्होंने अनावश्यक विलंब से बचने और शिकायतकर्ताओं को निस्तारण की प्रगति एवं स्थिति से समय-समय पर अवगत कराने को अनिवार्य बताया।जनसुनवाई के दौरान एक शिकायतकर्ता ने जाति प्रमाण पत्र न बनने की समस्या से जिलाधिकारी को अवगत कराया। इस पर जिलाधिकारी ने तत्काल तहसीलदार अकबरपुर पवन कुमार सिंह से जूम के माध्यम से वार्ता कर समस्या के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।इस अवसर पर जनपद स्तरीय समस्त अधिकारी, सभी उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया। जिलाधिकारी ने जनशिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

महाभारत के 'श्रीकृष्ण' की लाइफ में मचा बवाल?

बेटियों को पिता से आती है घिन! दूसरी आईएएस पत्नी ने नितीश भारद्वाज को लेकर किए कई बड़े खुलासे दूसरी शादी के बाद 'श्रीकृष्ण' के परिवार में बिगड़े हालात

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। टीवी के ऐतिहासिक और सुपरहिट पौराणिक धारावाहिक महाभारत में भगवान श्रीकृष्ण की भूमिका निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाले अभिनेता नितीश भारद्वाज आज भी उस किरदार के लिए याद किए जाते हैं। उनकी ऑनस्क्रीन भगवान की छवि आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है लेकिन इन दिनों अभिनेता अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर गंभीर विवादों में फंसे हुए हैं।

नितीश भारद्वाज ने पहली पत्नी मोनिशा पाटिल से साल 1991 में शादी की थी।

इस शादी से उनके दो बच्चे हुए लेकिन उनकी शादीशुदा लाइफ में तनाव शुरू हो गया। इसके बाद साल 2005 में दोनों ने तलाक ले लिया। वहीं एक्स वाइफ मोनिशा अपने दोनों बच्चों को लेकर नितीश से दूर चली गईं।

फिर साल 2009 में नितीश भारद्वाज ने IAS अधिकारी स्मिता गेट से दूसरी शादी की थी। इस शादी से उनकी जुड़वा बेटियां हैं। हालांकि ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चल सका और साल 2019 में दोनों अलग हो गए।

नितीश भारद्वाज ने अपनी दूसरी पत्नी स्मिता गेट पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने ये भी दावा किया था कि उन्हें उनकी बेटियों से दूर किया जा रहा है। अभिनेता ने इस संबंध में कानूनी शिकायत भी दर्ज कराई थी।

'श्रीकृष्ण' की जिंदगी में मची उथल-पुथल की चर्चा

वहीं हाल ही में एक इंटरव्यू में नितीश भारद्वाज ने फिर से कहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते उनकी जिंदगी में पूरी तरह उथल-पुथल मची हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी दोनों जुड़वा बेटियां उनसे नफरत करती हैं।

'बेटियों को अपने पापा से घिन आती है'

नितीश भरद्वाज ने कहा- दूसरी शादी में मैंने हर तरह का दुर्व्यवहार झेला है। अब हालत ये है कि मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए हैं। मेरी बेटियां मुझसे कहती हैं कि उन्हें मुझे पापा कहने में घिन आती है। नितीश भारद्वाज ने इन सबके लिए अपनी दूसरी पत्नी स्मिता गेट को जिम्मेदार ठहराया है और उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं।

IAS पत्नी स्मिता गेट ने खोली पति नितीश की पोल

-नितीश भारद्वाज के इस तरह की बयानबाजी के बाद अब स्मिता गेट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नितीश भारद्वाज के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि अभिनेता विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं।ने दावा किया है कि नितीश ने बच्चों की स्कूल की फीस तक कभी नहीं भरी। इसके अलावा नितीश पालन-पोषण में भी कोई आर्थिक सहयोग नहीं करते हैं।स्मिता गेट ने आगे कहा- नितीश भारद्वाज चाहते थे कि मैं IAS की नौकरी छोड़ दूं। जब मैंने ऐसा करने से इनकार किया तो उन्होंने घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी।-स्मिता ने कहा- नितीश भारद्वाज मुझे परेशान करने लगे थे। घर के सारे खर्च मुझे उठाने के लिए कहते थे और मुझसे पैसे का हिसाब भी मांगते थे। उन्होंने ही मुझसे तलाक की मांग की थी।

नितीश मुझसे पैसे मांगते थे

-स्मिता गेट ने कहा- जब मैं तलाक के लिए तैयार हुई तो मुझसे सहमति से तलाक के बदले पैसे मांगे गए जिसे मैंने ठुकरा दिया था। दूसरी तरफ नितीश भारद्वाज का कहना है कि उन्हें पिछले 5 साल से बच्चों से मिलने नहीं दिया गया है। वहीं स्मिता गेट ने इस दावे को भी गलत बताया है।स्मिता ने बताया- नितीश साल 2024 में दोनों बेटियों से मिलने आए थे। पुलिस और परिवार की मौजूदगी में ये मुलाकात हुई थी। बेटियां पिता से मिलकर भावुक भी हो गई थीं।

बेटियों के हक के लिए लड़ रही हैं स्मिता

-स्मिता गेट ने बताया कि वो और नितीश काफी समय से अलग रह रहे हैं। दोनों के तलाक का मामला चल रहा है। साथ ही बेटियों की कस्टडी का मामला भी अभी कोर्ट में है और वह आखिरी सांस तक अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ेंगी।-फिलहाल नितीश भारद्वाज और स्मिता गेट के बीच का ये गंभीर विवाद न्यायिक प्रक्रिया में है। दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए आरोपों की सच्चाई पर फैसला अब कोर्ट ही करेगा।

सड़क सुरक्षा माह में सख्ती के साथ जीवन बचाने के दिए मंत्र

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत मंगलवार को परिवहन विभाग ने जिले में सख्त प्रवर्तन अभियान चलाया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) गुलाबचंद एवं यात्री कर अधिकारी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान हेलमेट और सीटबेल्ट न पहनने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल तथा यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग जैसे मामलों में कुल 85 वाहनों का चालान किया गया। अभियान का उद्देश्य नियमों का उल्लंघन रोकने के साथ सड़क हादसों पर प्रभावी अंकुश लगाना रहा।

» **छोटी सी लापरवाही बन सकती है बड़ी दुर्घटना कारण: एआरटीओ**

» **अयोध्या में 85 चालान, हजार छात्रों को मिला जागरूकता का संदेश**

इसी क्रम में अमौना स्थित माधव सर्वोदय इंटर कॉलेज परिसर में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से व्यापक यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जिसमें करीब एक हजार छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एआरटीओ (प्रशासन) अयोध्या डॉ. आर.पी. सिंह रहे। उनके साथ एआरटीओ प्रवर्तन गुलाबचंद एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी उपस्थित रहे।

डॉ. आर.पी. सिंह ने विद्यार्थियों और उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की शपथ दिलाते हुए कहा कि छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को 'गोल्डन ऑवर' में अस्पताल पहुंचाने वाले 'नेक आदमी' की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ऐसे मददगार नागरिकों को कानूनी संरक्षण के साथ पारितोषिक भी दिया जाता है।

स्नेह भोज के बाद संवाद की मेज़ पर हुई चर्चा

जिला सूचना अधिकारी की सहभागिता बनी खास

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। नए वर्ष के अवसर पर अयोध्या के स्टार सिटी होटल में आयोजित पत्रकारों के स्नेहभोज ने केवल औपचारिक मुलाकात का दायरा नहीं निभाया, बल्कि प्रशासन और मीडिया के बीच संवाद, संवेदना और समन्वय का जीवंत उदाहरण भी प्रस्तुत किया। पत्रकार डॉ. बृजेश कुमार सिंह द्वारा आयोजित इस स्नेहिल आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में जिला सूचना अधिकारी अनुराग रंजन की उपस्थिति रही।

जिला सूचना अधिकारी ने सूचना तंत्र को और अधिक पारदर्शी व संवेदनशील बनाने की प्रतिबद्धता ने उनकी कार्यशैली की सकारात्मक छवि को रेखांकित किया । स्नेहभोज में पारंपरिक स्वाद की झलक भी दिखी, जहां बाटी-चोखा, दाल और चावल ने आत्मीयता को और गाढ़ा किया। प्रेस क्लब अध्यक्ष सुरेंद्र श्रीवास्तव सहित राजेन्द्र सोनी, अशोक तिवारी, के.के. मिश्रा, रूपेश श्रीवास्तव, सुबोध श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव 'अज्जू', प्रदीप पाठक, समीर शाही, अभिषेक श्रीवास्तव, मयंक शुक्ला, प्रशांत शुक्ला, अंतरिक्ष तिवारी, निमिष गोस्वामी, आशु श्रीवास्तव, संदीप श्रीवास्तव, ज्ञानेन्द्र मिश्रा सहित दर्जनों पत्रकारों की उपस्थिति ने आयोजन को गरिमा प्रदान की।

हर घर मने लोहड़ी, खुशी रल के मनाय होवे...

धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का पर्व

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। मकर संक्रांति के पूर्व मंगलवार को शहर के कई मोहल्लों में लोगों ने धूमधाम से लोहड़ी का पर्व मनाया। सुंदर मुंदरीय होए तेरा कौन विचारा होए दूल्हा भट्टी वाला हुए सरीखे गीतों पर नाचते गाते लोहड़ी पर्व धूमधाम से मनाया गया। भांगड़ा, ढोल, साउंड पर बजते हिट पंजाबी गीतों के साथ शहर में जगह-जगह लोहड़ी का उल्लास बिखरा। शाम होते ही तमाम इलाकों में जली लोहड़ी में मूंगफली, मक्के के लावे, रेवड़ी, गजक तिल और मिठाइयां छुड़ाई गई। साउंड पर बजते हिट पंजाबी गीतों के साथ शहर में जगह जगह उल्लास बिखरा।

सुंदरनगर कॉलोनी, बालक राम कॉलोनी, मौदहा, चौक, लाजपत कॉलोनी, गुरुद्वारा नजर बाग, खिड़की अली बेग स्थित गुरुद्वारा दुख निवारण में उत्साह और उमंग के बीच उत्सवी माहौल में पर्व का लोगों ने आनंद उठाया। इस दौरान गुड़, मूंगफली, मक्का, तेल व गजक आदि चढ़ाया गया। गुरुद्वारा दुख निवारण में हुए लोहड़ी पर्व में राजेंद्र सिंह, अमनदीप सिंह वीसी, प्रतिपाल सिंह पाली ने बताया कि दिन भर लोहड़ी के बाद लोगों ने हर्षोल्लास के साथ पर्व को मनाया तत्पश्चात अग्नि को लोगों ने गुड़, लावा आदि सामान भेंट किया।

संक्रमित मरीजों ने जिन 3 जगहों का दौरा किया था, उसे हाई रिस्क जोन में रखा गया

बंगाल में निपाह वायरस का संक्रमण

2 नर्स वेंटिलेटर पर, 102 लोगों को किया गया क्वॉरंटीन

स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस ने तेजी से पैर पसारने शुरू कर दिये हैं. 2 संदिग्ध नर्सों को वेंटिलेटर पर रखा गया है, तो उनके संपर्क में आये लोगों की ट्रेसिंग शुरू हो गयी है. डॉक्टर समेत 4 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है. वहीं, 102 लोगों को कोरेंटिन कर दिया गया है. नर्सों के आवास को अस्थायी रूप से सील कर दिया गया है.

निपाह वायरस से संक्रमित 2 नर्सों के सैंपल पुणे लेबोरेटरी भेजे गये थे. रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है.

डॉक्टर समेत 4 स्वास्थ्यकर्मी आइसोलेशन में

अस्पताल सूत्रों ने बताया कि वायरस से संक्रमित नर्स के संपर्क में आये डॉक्टर समेत 4 स्वास्थ्यकर्मियों को आइसोलेशन में भेजा गया है. 50 लोगों के नमूने एकत्र किये गये हैं. नर्स का घर भी अस्थायी रूप से सील कर दिया गया है. कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम चल रहा है.

इमरजेंसी से निबटने के लिए आईडी अस्पताल तैयार

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, इमरजेंसी से निबटने के लिए बेलियाघाटा आईडी अस्पताल को तैयार किया गया है. यहां 10 इमरजेंसी बेड के साथ वार्ड में 68 बेड तैयार रखे गये हैं. संक्रमित मरीजों के संपर्क में आये 48 लोगों की सूची तैयार कर ली गयी है. संक्रमित मरीजों ने जिन 3 जगहों का दौरा किया था, उसे हाई रिस्क जोन में रखकर एहतियाती कदम उठाये जा रहे हैं.

इसके बाद प्रभावित इलाकों के निजी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर से लेकर कर्मचारी तक के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है. डॉक्टर पीपीई किट पहनकर काम कर रहे हैं. अब तक 102 लोगों को कोरेंटिन किया गया है.

कोबरा से किया खिलवाड़, तीन बार डसने से बुजुर्ग की मौत

स्वराज इंडिया ब्यूरो

रामपुर। रामपुर जिले में सांप से खिलवाड़ एक व्यक्ति की जान ले बैठा। बिलासपुर तहसील के पिपलिया गोपाल गांव में 50 वर्षीय जी. राज सिंह की उस वक्त मौत हो गई, जब वह करीब 6 फुट लंबे जहरीले कोबरा को पकड़कर उसके साथ करतब दिखा रहे थे। इसी दौरान कोबरा ने उन्हें एक के बाद एक तीन बार डस लिया, जिससे जहर तेजी से शरीर में फैल गया।

घटना गांव की सड़क पर हुई, जहां कोबरा दिखने के बाद जी. राज सिंह ने उसे उठाकर खेलना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उन्हें बार-बार रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने खुद को फ़कीर बहादुरफ़ बताते हुए सांप को गले में लपेट लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कुछ ही पलों में कोबरा ने उनके हाथ, कान और गर्दन पर हमला कर दिया। परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर सांप को सुरक्षित पकड़ लिया।

➪ ग्रामीणों की मनाही के बावजूद गले में लपेटा जहरीला कोबरा

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

इस दर्दनाक हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सांप के साथ की जा रही लापरवाही साफ देखी जा सकती है। रामपुर के डीएफओ प्रणव जैन ने बताया कि इंडियन स्पेक्टाकल कोबरा भारत के चार सबसे जहरीले सांपों में शामिल है। बिना प्रशिक्षण और सुरक्षा के ऐसे सांपों से छेड़छाड़ जानलेवा हो सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सांप दिखने पर खुद रेस्क्यू करने की कोशिश न करें और तुरंत वन विभाग या प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम को सूचना दें।

ईरान में खामेनेई शासन के खिलाफ जनविद्रोह

- 2571 की मौत का दावा, 18 हजार से ज्यादा गिरफ्तार
- आज हो सकती है प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी
- ट्रंप की चेतावनी, फांसी दी तो होगी कड़ी कार्रवाई

स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क, तेहरान/वॉशिंगटन। ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के शासन के खिलाफ जनता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। देशभर में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी हैं और लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि सरकारी कार्रवाई में अब तक 2,571 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 18,100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मृतकों में 2,403 प्रदर्शनकारी, 147 सरकारी समर्थक और 12 बच्चे शामिल बताए गए हैं।

पहली बार प्रदर्शनकारी को फांसी

ईरानी सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाते हुए पहले ही मौत की सजा देने का ऐलान किया था। इसी कड़ी में अब 26 वर्षीय प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक, इरफान को आज ही फांसी दी जा सकती है। यदि ऐसा होता है, तो मौजूदा आंदोलन में यह पहली फांसी होगी।

अमेरिका का दबाव, व्यापारिक देशों को टैरिफ की धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए चेतावनी दी है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा, उस पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है। ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों को सच्चे देशभक्त बताया। वहीं रूस ने अमेरिका की इस नीति की आलोचना करते हुए कहा है कि ईरान के आंतरिक मामलों में दखल और सैन्य धमकियां स्वीकार्य नहीं हैं।

ट्रंप की सख्त चेतावनी 'मदद आ रही है'

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मदद आ रही है और ईरान में रह रहे अमेरिकियों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई, तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। हालांकि, कार्रवाई के स्वरूप को लेकर उन्होंने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी।

लारीजानी का ट्रंप-नेतन्याहू पर आरोप

ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव और पूर्व संसद अध्यक्ष अली लारीजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर सीधे आरोप लगाए। लारीजानी ने लिखा कि ईरान के लोगों के मुख्य हत्यारे ट्रंप और नेतन्याहू हैं।

निर्वासित युवराज रेजा पहलवी की अपील

निर्वासित युवराज रेजा पहलवी ने सोशल मीडिया पर ईरान की जनता से संघर्ष जारी रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि दुनिया अब ईरानी जनता की आवाज सुन रही है और इस दमनकारी शासन को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि हालात सामान्य हैं।